(c) if so, whether Government have issued any fresh instructions to its Ministers to remain in Delhi and attend the work relating to their concerned Ministry/Department; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR MR. JANARTHA-NAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Prime Minister has rescently empahsised that the absence of Ministers and various Government functionaries for long period should be avoided, as it creates dislocation and delay in disposal of Government business. The Prime Minister has advised that as for as possible the delegations to foreign countries should not be very large.

सांसदों के "पत्रों का उत्तर दिया जाना

383. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि संसद-सदस्यों के पत्रों का समय पर उत्तर नहीं दिया जाता या उत्तर दिया ही नहीं जाता;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि सरकारी विभाग संसद-सदस्यों के प्राप्त हुए पत्रों का अंतरिम तथा अंतिम उत्तर देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का भी पालन नहीं करते;

(ग) क्या संसद-सदस्यों ने इस संबंध में सरकार से कोई शिकायत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त अधिकांश पत्रों का उत्तर मार्ग-दर्शी सिद्वांतों में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर भेजा जाता हैं। कुछ मामलों में, जहां पत्र से संबंधित कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालयों से सूचना एकत्र की जानी होती हैं, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने में विलय हो सकता हैं। तथापि, ऐसे मामलों में सामान्यत: एक पखवाड़े के भीतर अंतरिम उत्तर भेज दिया जाता हैं।

(ग) और (घ) जी हां, इस संबंध संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने से संबंधित अनुदेश समय-समय पर दोहराये गए है। कार्मिक, लोक शिकायल तथा पेंशन राज्य मंत्री ने भी भारत सरकार के मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावतियां विधिवत् रूप से भेज दी जाएं। और इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल सचिव ने भी इस संबंध में दिनांक 23.5.98 को और फिर 9.9.98 को भारत सरकार के सभी सचिवों को निदेश जारी किये हैं।

मंत्रियों के निजी स्टाफ के विरूद्व भ्रष्टाचार के आरोप

384. **श्री चीमनभाई हरीभाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों के निजी स्टाफ के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे है और उन्हे अपने-अपने मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्व किस प्रकार के आरोप हैं तथा उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इस मंत्रियों ने ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देकर तथा उन्हे बचा कर सरकार की छवि को खराब कर दिया हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करने की क्या मजबूरी हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उसके द्वारा वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के विरूद्व ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर दिया जाना

385. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं संसद-सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने की कार्यवाही में किए गए प्रावधानों में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को उक्त प्रावधानों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही हैं, ताकि संसद-सदस्यों के पत्रों का शीघ्र उत्तर दिया जा सके?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का तत्काल उत्तर देने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्वति नियम-पुस्तिक में निर्धारित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं। परन्तु, सामान्यत: राज्य सरकारें इस संबंध में अपने दिश-निर्देश निर्धारित करती हैं।

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री ने दिनांक 26.12.97 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस संबंध में संसद सदस्यों की चिन्ता को दोहराते हुए अनुरोध किया था कि वे अपनी-अपनी सरकारों के दिशा/निर्देश/अनुदेश जारी करें कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने के संबंध में वे केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्वति नियम-पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुदेशों के आधार पर समुचित कार्य पद्वति का अनुपालन करें।

भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालतें

386. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार तथा वित्तीय घोटालों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु देश में विशेष अदालतें स्थापित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान हेतु विशेष अदालतें स्थापित करते समय उच्चतम न्यायालय की राय पर विचार किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामलें में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम,1998 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें, दोनों ही उपर्युक्त अधिनियम में विर्निदिष्ट अपराधों की सुनवाई के लिए, विशेष न्यायाधीश को नियुक्त कर सकती हैं। दंड-प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सरकारें विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के शीघ्र निबटाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तथा राज्य-सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का सुझाव देते हुए प्रधान मंत्री ने जून, 1997 में सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

(घ) चूंकि विशेष न्यायालय राज्य-सरकारों द्वारा गठित किए जाने हैं, अत: इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

मंत्रालयों/विभागों की संख्या में कमी

387. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों का विलय करके केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की संख्या में कमी करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो विलय किए गए मंत्रालयों और विभागों का ब्यौरा क्या है;